सेज राजस्थान की जरुरत . टाई

<u>1000 से भी आई टी क्षेत्र के व्यवसायी व प्रोफशनल के हस्ताक्षर युक्त एक</u>
<u>समर्थन पत्र मुख्यमन्त्री श्रीमती वसुन्धरा राजे को पेश किया</u>

सेज क्यों ?

सेज के मॉडल को अनेकों एशियाई देशों जैसे चीन, मलेशिया, ताईवान, श्रीलंका आदि द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सफलतापूर्वक लागू किया किया है। सेज को चीन उदार व्यापारिक नीतियां व सहायतापूर्ण वातावरण प्रस्तुत करके सबसे अधिक सफलतापूर्वक लागू कर पाया है। चीन ने सेज के मॉडल को अपने देश के चार प्रान्तों शेनझेन, जुहाई, शान्तो व जियामेन में सफलतापूर्वक लागू किया है जिसका फायदा उसने आर्थिक उन्नति प्राप्त कर हासिल किया है। इससे उसे विकास के नए आयाम मिले हैं।

एफडीआई के तथ्यात्मक विश्लेषण को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि द ि ण एशिया कुल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत मूल्य के एफडीआई आकर्षित करता है। इसकी तुलना में चीन में घरेलू उत्पाद का एफडीआई करीब चार प्रतिशत है। इस सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण सेज की सफल क्रियान्विति या कहा जाय तो विशिष्ट आर्थिक जोन के अन्तर्गत विश्व स्तर के निवेश वातावरण पर अधिक ध्यान देना जिससे विकास की गति बढ़ सके।

चीन के पांच प्रान्त शेन्झेन, जुहाई, शान्तो, जियामेन व हाइनेन जिनको सेज प्रान्तों के नाम से जाना जाता है वे करीब 70 बिलियन डालर के संचित एफडीआई के साथ चीन के निर्यात का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं व 8 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को प्रत्य रोजगार मुहैया कराते हैं। (भारत में वर्तमान में सेज के माध्यम से एक लाख प्रत्य रोजगार ही उपलब्ध)

सेज को परिभाषित किया जा सकता है ''एक ऐसी औद्योगिक संपदा जिसकी विशेषज्ञता निर्यात हेतु उत्पादन, उद्यमियों को खुली व्यावसायिक स्थितियां प्रदान करना व उदार नियमन प्रक्रिया लागू करना हो''। चीन में सेज को पीआरसी द्वारा विदेशी निवेश, रोजगार के अवसर बढ़ाना, तकनीकी ज्ञान बढ़ाना व इतने वर्षों में ऑपरेशन के प्रारंभ में उपलब्ध कराये गए महत्वपूर्ण कर छूटों की वसूली के लिए राजस्व प्राप्त करने हेतु गठित किए गए। सेज विदेशी निवेश अभिमुखी `त्र है जो प्राथमिक तौर पर संसाधित वस्तुओं के निर्यात का ध्यान रखते हैं तथा जो विज्ञान उ ोग का प्राथमिक नीतियों व विशेष प्रबंधन प्रणालियों से व्यवसाय व लाभों का एकीकरण करता है।

चीन में सेज इकाइयों से कुल निर्यात 45 प्रतिशत व भारत में 5 प्रतिशत है। इसी प्रकार श्रीलंका में यह आंकड़ा 40 प्रतिशत है। सेज ने चीन को व्यापक माल निर्यात में अपना हिस्सा तीन गुना यानि पिछले 20 वर्षों में 4 प्रतिशत करने में सहायता प्रदान की है इसका श्रेय सेज को सफलतापूर्वक लागू करना को जाता है। जहां भारत पिछले दशक में एफडीआई में 4 बिलियन यू एस डालर को आकर्षित करने में सफल हो पाया है वही चीन ने पिछले 5 सालों में औसत एफडीआई में करीब 50 बिलियन यूएस डॉलर प्रति वर्ष प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है (75 प्रतिशत अधिक का अनुमान है)। 1994—99 के दौरान चीन में एफडीआई के कारण कुल रोजगार सृजन विदेशी कम्पनियों द्वारा 12 मिलियन व स्थानीय निजी कम्पनियों के द्वारा 20 मिलियन अतिरिक्त हुआ है।

चीन का पहला व सबसे अधिक सफल सेज प्रान्त शेनझेन ने सन् 2004 में 7100 यूएस डॉलर से अधिक प्रति व्यक्ति कुल घरेलु उत्पाद अर्जित किया है जो कि सभी अन्य चीनी प्रान्तों से अधिक है (राष्ट्रीय औसत का पांच गुना)। सन् 2010 के लिये इसका लक्ष्य 12000 डॉलर है।

जब समग्र चीन अपनी खराब आर्थिक स्थिति से उभरने की कोशिश कर रहा है उस समय भी शेनझेन की अर्थव्यवस्था 14—17 प्रतिशत प्रति वर्ष की तीव्र गति से बढी। शेनझेन को वास्तविक विश्व शहर के रूप में विकसित किया गया है जहां 1.65 मिलियन की जनसंख्या में से करीब 0.8 मिलियन अप्रवासी है।

पीआरसी(चीन) से इसके अन्तर्गत आधारिक संरचना को विकसित करने व सुधार करने हेतु और साथ ही दूसरी आधारिक संरचना सुविधायें जो कि सेज को बढावा देने में सहयोगी होती हैं जैसे वित्तीय सेवायें (बैकिंग व बीमा) में महत्वपूर्ण स्त्रोतों का निवेश करता है। सेज राष्ट्रीय योजनाओं में अलग से सूचीबद्ध है (वित्तीय योजना सम्मिलित) व आर्थिक प्रशासन में इसके पास प्रान्त स्तरीय अधिकार है। चीन में सेज 200 वर्ग किलोमीटर (50000एकड) से अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है।

चीन की सफलता से प्रेरित होकर भारत भी सेज से लाभ उठाने की तैयारी कर रहा है जिससे एफडीआई को आकर्षित करके व्यावसायिक व आर्थिक गतिविधियों को बढावा मिल सके व वृहद् स्तर पर रोजगार के साधन मुहैया करा सके। भारत को सेवा व उत्पादों दोनो का ही निर्यात केन्द्र बनाया जा सकता है। इसके लिये भारत सरकार ने विस्तृत सेज एक्ट विशाल सेज क्षेत्र का निर्माण करने के लिये घोषित किया है। वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार सेज हेतु 2500 एकड न्यूनतम क्षेत्र व विशिष्ट उत्पाद सेज के लिये 250 एकड क्षेत्र अनिवार्य है। यह कदम विकास की उच्च लागत को हतोत्साहित करने के लिये उठाया गया है।

मैकिन्से के अध्ययन के अनुसार भारत में अगले 5 वर्षो में एफडीआई से 100 बिलियन यूएस डॉलर आकर्षित करने का सामर्थ्य है। एफडीआई में वृद्धि अधिकतर निर्यात अभिमुखी इकाइयों में जिसमें सेज सबसे अधिक लाभान्वित होगा व आधारिक संरचना की उन्नति आयेगी। यह अनुमान लगाया गया है कि अकेले एफडीआई कुल राष्ट्रीय घरेलु उत्पाद को 2 से 3 प्रतिशत प्रति वर्ष बढाने में सफल होगा। सन् 2003–04 के बीच भारत ने अपनी एफडीआई वरीयता 15वीं से तीसरे स्थान पर जो कि अमेरीका के ठीक निचले स्थान पर आता है, पर सुधार ली है। एफडीआई के करीब एक लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार अवसरों का प्रति वर्ष सृजन की सम्भावना है यद्यपि अस्थायी वित्तीय प्रोत्साहन विश्व प्रमुखों से कुछ निवेश प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकता हैं तथापि एफडीआई को धारणीय स्तर पर आकर्षित करने के लिये विश्व स्तर पर आधारिक संरचना दीर्घावधि घटक है। सेज इन कम्पनियों को ऐसी आधारिक संरचना के द्वारा सही मंच प्रदान करता है।

राजस्थान में सेज

- यह एक सर्व मान्य तथ्य है कि अत्यधिक कुशल जन शक्ति व बेहतर कानून प्रणाली के होते हुये भी भारत विश्व प्रमुखों को आकर्षित करने में चीन से बहुत पीछे है। इसके पीछे निम्न गुणवत्ता आधारिक संरचना को उत्तरदायी माना जाता है। यह साबित हो चुका है कि विदेशी कम्पनियाँ भारत में निवेश करने के लिये तैयार है परन्तु इसके लिये आधारिक संरचना गति अवरोधों को दूर किया जाना चाहिये महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी इसकी गवाह है।

- श्री नन्दन नीलकेनी, सीईओ व एमडी इन्फोसिस के अनुसार सेज प्रोजेक्ट विश्व स्तर आधारिक संरचना उपलब्ध कराती है जिससे विश्व खिलाड़ी के रूप में हमारी स्थिति सुदृढ़ होती है।

- विश्व स्तर आधारिक संरचना संचार सुविधाओं, उर्जा, जल इत्यादि की निरन्तर उपलब्धता, उच्च गुणवत्ता की सामाजिक आधारिक संरचना जैसे स्कूल, कालेज, हास्पिटल, हाउसिंग, मनोरंजन इत्यादि सुविधाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिये।

- विदेशी प्रमुखों के लिये राजस्थान उच्च गुणवत्ता आधारिक संरचना व कानून व्यवस्था के चलते आकर्षक गतव्य स्थल है।

- उत्तरी भारत के अन्य स्थान विशीर्ण आधारिक संरचना व संचालन की उच्च लागत के कारणों से त्रस्त है। राजस्थान में ऐसी स्थिति नहीं है इसी वजह से सेज के लिये राजस्थान का जयपुर शहर स्थानीय तथा विश्व कम्पनियों द्वारा निवेश के लिये आकर्षक स्थान है।

- NASCOMM सर्वेक्षण के अनुसार सन् 2008 तक IT / ITES क्षेत्र में 2 करोड प्रत्यक्ष व 2 करोड अप्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन होगा। इसमें कुशल जनशक्ति व एनसीआर क्षेत्र में अच्छी संयोजना भी होगी जो आने वाले प्ज ६ प्ज्म्ै निवेश के प्रमुख हिस्से को आकर्षित करने के लिये आदर्श है।

- करीब 10000 अभियान्त्रिकी ग्रेजुएट प्रति वर्ष राजस्थान से पास होते है जिनमें से अधिकांश को प्रस्तावित सेज में रोजगार के अवसर प्राप्त करने की सम्भावनायें बढ जाती है।

- उम्मीद है कि प्रस्तावित सेज द्वारा जयपुर में अगले 3 वर्षो की अवधि में IT / ITES क्षेत्र में एक लाख प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। सर्वेक्षणों के अनुसार हर प्रत्यक्ष रोजगार के लिये एक लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगें। अतः एक लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने का अतिरिक्त सामर्थ्य है।

- इसके संभार तन्त्र के लाभों के कारण, जयपुर का सेज उत्तरी भारत के लिये 'संभार तन्त्र केन्द्र' बनने का अनुपम अवसर प्रदान करता है इसमें अर्द्ध कुशल व अकुशल कर्मचारियों हेतु रोजगार सृजन की सम्भावना रहेंगी।

- प्रस्तावित सेज जयपुर को निम्न मूल्य औद्योगिक गतिविधियों से उच्च स्तर 'औद्योगिक केन्द्र' में परिवर्तन में सहायक होगा।

- राज्य व राष्ट्रीय औसत की तुलना में उच्च आर्थिक वृद्धि होगी। चीन के सेज का प्रति व्यक्ति कुल घरेलु उत्पाद राष्ट्रीय औसत से करीब 4–6 गुना व वृद्धि राष्ट्रीय औसत से दुगनी है।

- बेहतर रोजगार के अवसर, बेहतर शिक्षण व चिकित्सा आधारिक संरचना की उपलब्धता व क्षेत्र में उच्च आर्थिक गतिविधियों के कारण स्थानीय समुदाय भी लाभान्वित होगा।

- सरकार को भी हाउसिंग, शिक्षा, पर्यटन आदि में वृहद् स्तर पर आर्थिक गतिविधियों के कारण लाभ होगा। वृहद् स्तर पर एफडीआई के परिणाम स्वरूप प्रवासी व निरन्तर आने वाले विदेशी यात्री जयपुर आयेगें जिससे पर्यटन व सम्बन्धित उद्योगो को बहुत लाभ होगा। भारी रोजगार अवसरों की उपलब्धता के कारण सामाजिक बोझ भी बेरोजगारी दर घटाने में सहायक होगा।

हरियाणा के मुख्यमन्त्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा के अनुसार राज्यों में सेज की स्थापना की जानी चाहियें तथा प्रत्येक जोन में विभिन्न निर्यातोन्मुखी गतिविधियों को बढावा दिया जाना चाहिये। आउट सोर्स कॉल सेन्टर्स रोजगार के स्वर्णिम अवसर प्रदान करते है साथ ही विदेशी विनिमय को भी बढावा मिलता है। इसका एक प्रमुख कारण उन्होने बताया कि भारत में वृहद् स्तर पर बोली जाने वाली अंग्रेजी भाषा का लाभ मिलता है।

जैम प्दकपंद म्गचतमे

छवअमउइमत 18ए 2005ए च्ंहम 1

इन्हीं फायदों को आइटी क्षेत्र की जरुरतों को ध्यान में रखते हुए टाई राजस्थान चेप्टर के प्रतिनिघि मंडल, ने आज मुख्यमन्त्री श्रीमती वसुन्धरा राजे से भेंट की । तथा सेज की आवश्यकतों को अपना समर्थन प्रदान किया । प्रतिनिघि मंडल में टाई अध्यक्ष श्री अजय डाटा, उपाघ्यक्ष श्री राजेश मून्दड़ा, सचिव श्री महावीर प्रताप शर्मा व जुल्फिकार हक, कार्यकारी निदेशक ने अपनी तरफ से 1000 से भी अधिक आई टी क्षेत्र के व्यवसायी व प्रोफशनल के हस्ताक्षर युक्त एक समर्थन पत्र पेश किया । इस अवसर पर शासन सचिव श्री रोहित सिंह भी मौजूद थे ।

इस मुलाकात में टाई प्रतिनिघि मंडल ने सेज की शीध्र आवश्यकता पर बल दिया । इन आइ टी कम्पनियों द्वारा सेज में निवेश की उत्सुकता दिखाइ तथा अजय डाटा ने मुख्यमंत्री को टाई द्वारा ग्लोबल आइ टी प्रमोशन के कार्यों की जानकारी दी । राजस्थान को देश तथा विदेश में आई टी के क्षेत्र में प्राथमिक गंतव्य स्थल बनाने में सरकार को सहायता तथा टाई के हर संभव प्रयास को भरोसा दिलाया ।